सांध्य दैनिक 4PM

जिद...सच की

www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_Sanjay YouTube @4pm NEWS NETWORK

● वर्ष: 8 ● अंक: 174 ● पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, शनिवार, 30 जुलाई, 2022

मूल्य ₹ 3/-

अपना भाग्य स्वयं नियंत्रित करिए नहीं तो कोई और करने लगेगा।

-जैक वेल्च

विकास पर ध्यान दे भाजपा... 8 | लोक सभा चुनाव की जंग को अखिलेश... 3 | विकास के मोर्चे पर सरकार फेल... 7

पहले चार जिलों को मिलती थी बिजली हमने दूर किया भेदभाव : सीएम योगी

» हर घर बिजली पहुंचाने का पूरा किया लक्ष्य, सभी गांव और जिले बन गए हैं वीआईपी

» विद्युत उत्पादन में प्रदेश को बनाना है आत्मनिर्भर जनता तक पहुंच रही हैं सरकारी सुविधाएं

» मुख्यमंत्री ने 17 पारेषण एवं वितरण उपकेंद्रों का किया शिलान्यास और लोकार्पण

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में 2,723.20 करोड़ की लागत के 17 विद्युत पारेषण एवं वितरण उपकेन्द्रों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमने विद्युत वितरण में भेदभाव को दूर किया है। पहले चार जनपदों को बिजली मिलती थी, शेष 71 जनपद अंधेरे में डूबे रहते थे लेकिन पिछले पांच वर्षों में प्रदेश में कोई वीआईपी जनपद नहीं है बल्कि प्रदेश का हर गांव और जनपद वीआईपी है।

उन्होंने कहा कि उज्ज्वल भारत के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए बिजली महोत्सव व ऊर्जा महोत्सव मनाया जा रहा है। 1.21 लाख गांव में आजादी के बाद भी बिजली नहीं पहुंच पाई थी। हमने हर घर बिजली के लक्ष्य को पूरा किया है। अब सभी जगह रोस्टर के अनुसार बिजली दे रहे हैं। अगले पांच साल में अपनी बिलिंग और कनेक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाना विभाग के लिए चुनौती है। हमें विद्युत उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनना है। उन्होंने कहा कि पावर कॉरपोरेशन बिना भेदभाव के बिजली उपलब्ध कराएगा। वास्तव में लोकतंत्र का सबसे मजबूत आधार यही है जब जनता को शासन व प्रशासन से मिलने वाली सुविधाएं, उसकी आवश्यकता के अनुरूप बिना भेदभाव के उसे प्राप्त हो जाएं। बिजली महोत्सव के इस कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर, अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी और पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

पड़ोसी देशों को निर्यात कर रहे बिजली: शर्मा

ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि पिछले छह दिन से ऊर्जा महोत्सव मनाया जा रहा है। आज महोत्सव के समापन का दिन है। विकास में ऊर्जा बड़ा कारक रही है। देश में पानी, बिजली और सड़क राजनीतिक मुद्दा बनता है। देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए ऊर्जा का विकास, बिजली की निर्बाध आपूर्ति आवश्यक है। पहले देश बिजली की कमी के लिए जाना जाता था और 5 से 10 प्रतिशत की कमी बनी रहती थी। अब हम पड़ोसी देशों को बिजली निर्यात कर रहे हैं। सौभाग्य योजना के तहत यूपी को 1.43 करोड़ कनेक्शन दिए गए हैं।

अब महाराष्ट्र में राज्यपाल कोश्यारी के बयान पर बवाल, विपक्ष हमलावर

» उद्धव ठाकरे ने पूछा, कब घर भेजा जाएगा राज्यपाल को

» कांग्रेस और एनसीपी ने माफी मांगने की मांग की भाजपा विधायक ने भी जताया विरोध

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर महाराष्ट्र में बवाल मच गया है। शिवसेना, मनसे, एनसीपी और कांग्रेस ने उनके गुजराती-राजस्थानी वाले बयान को लेकर हमले तेज कर दिए हैं। वहीं भाजपा विधायक ने भी उनके बयान पर अपनी असहमति जताई है।

पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्यपाल के बयान ने मराठी मानुषों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। राज्यपाल समुदायों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है कि उन्हें घर कब वापस भेजा जाएगा? मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि मराठी आदमी को मूर्ख मत बनाओ। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। भाजपा विधायक आशीष शेलार ने भी बयान पर असहमति जताई है। वहीं राज्यपाल ने अपने बयान को वापस ले लिया है और कहा है कि उनका इरादा मराठी लोगों के योगदान को कम आंकना नहीं था।

मराठियों को कम आंकने के बयान पर घिरे राज्यपाल, दी सफाई

क्या है मामला

मुंबई में एक लोकल कार्यक्रम में शामिल हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा था कि कभी-कभी मैं यहां लोगों से कहता हूं कि महाराष्ट्र में विशेषकर मुंबई-ठाणे से गुजरातियों और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहां पैसा बचेगा ही नहीं। ये मुंबई आर्थिक राजधानी कहलाती, वो आर्थिक राजधानी कहलाएगी ही नहीं।

अधिकांश लोगों का कोर्ट तक पहुंचना टेढ़ी खीर : चीफ जस्टिस

» जानकारी के अभाव में दर्द सहने को हैं मजबूर

» अधीनस्थ न्यायपालिका को तत्काल करना होगा मजबूत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन ने आज व्यवस्था और न्याय को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि न्याय की आस लेकर कोर्ट में पहुंचने वालों की संख्या काफी कम है। जानकारी के अभाव में अधिकांश लोग दर्द सहने को मजबूर हैं।

अखिल भारतीय जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अधीनस्थ न्यायपालिका को फौरन मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने न्याय तक पहुंचने की प्रक्रिया को मुक्ति का हथियार बताया और कहा कि आबादी का काफी छोटा हिस्सा है जो न्याय के लिए कोर्ट में पहुंच रहा है। एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके पास या तो जानकारी का अभाव है या फिर साधनों से वे वंचित हैं और इसलिए न्याय के लिए अदालत की दर तक पहुंचना उनके लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलाजी एक बड़े सहायक के तौर पर उभरा है। आधुनिक भारत के निर्माण का मकसद समाज में फैली निराशा को जड़ से खत्म करने का है। लोकतंत्र की परियोजना सभी के लिए मंच उपलब्ध कराना है।

यूपी में पेट्रोल-डीजल पर नहीं बढ़ेगा वैट

» न ही जनता पर लगाया जाएगा कोई नया कर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर वैट न बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निकट भविष्य में भी पेट्रोल-डीजल पर वैट में कोई वृद्धि नहीं होगी। न ही जनता पर कोई नया कर लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास पर राज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ राजस्व संग्रह की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1.50 लाख करोड़ रुपये के जीएसटी और वैट संग्रह संग्रह लक्ष्य को पूरा करने के साथ जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों की संख्या में 26 से बढ़ाकर 30 लाख करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए इस समय पेट्रोल-डीजल की सबसे कम कीमत यूपी में है। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में भी वैट में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में राजस्व संग्रह के लिए जोनवार समीक्षा करते हुए अलग-अलग ज़ोन की क्षमता के अनुसार राजस्व संग्रह को बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नियोजित प्रयासों से प्रदेश के राजस्व संग्रह में सतत वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2017.18 में प्रदेश का कुल राजस्व संग्रह 58,700 करोड़ रुपये था जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर लगभग 1 लाख करोड़ रुपये हो गया है। चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लक्ष्य 31,786 करोड़ रुपये के सापेक्ष 32,386 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ है। मुख्यमंत्री ने राजस्व संग्रह की स्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि जनता से कर के रूप में जमा एकत्रित राशि को प्रदेश के विकास पर खर्च किया जाएगा। बैठक में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल, अपर मुख्य सचिव वित्त प्रशांत त्रिवेदी, प्रमुख सचिव राज्य कर नितिन रमेश गोकर्ण, सहित अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री हर महीने करेंगे जोनवार समीक्षा

मुख्यमंत्री राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए शासन स्तर से फील्ड के अधिकारियों को साप्ताहिक लक्ष्य देने और उसकी साप्ताहिक समीक्षा भी करने के निर्देश दिए। उन्होंने जोन में प्रवर्तन की कार्रवाई तथा राजस्व संग्रह की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वह खुद हर महीने जोनवार समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि जीएसटी को लेकर गोरखपुर और बस्ती मंडल जैसे कई क्षेत्रों में अभी जागरूकता का अभाव है। इसके लिए फील्ड स्तर के अधिकारियों को विशेष प्रयास करने होंगे।

अधिकांश जोन की कार्यशैली को बेहतर बनाने की आवश्यकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकांश जोन की कार्यशैली को और बेहतर करने की आवश्यकता है। राजस्व संग्रह में आगरा, बरेली, गोरखपुर, अयोध्या जोन ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सराहनीय प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के अनेक बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यहां जीएसटी संग्रह बढ़ाने की बहुत संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री कार्यशैली को बेहतर करने के साथ कर चोरी पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कर चोरी करने वालों के खिलाफ छापेमारी की कार्यवाही करने और इंटेलिजेंस को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए।

उत्तराखंड में संगठन में बड़ा फेरबदल, मदन कौशिक से बीजेपी ने छीनी कुर्सी

» प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर महेंद्र भट्ट को सौंपी कमान

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

देहरादून। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर महेंद्र भट्ट को कमान सौंप दी है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने औपचारिक तौर पर पत्र जारी करते हुए बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भट्ट को उत्तराखंड भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया और इस आदेश में यह भी कहा गया यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू की जा रही है।

लोकसभा चुनाव 2024 और उससे पहले कई राज्यों में होने जा रहे चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने इस बार संगठन के भीतर चुनावों को टालकर सीधे अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है, जैसा कि माना जा रहा था। इससे पहले ही राज्य में प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की अटकलें तब पैदा हुई थीं, जब भट्ट के साथ ही कौशिक और अन्य भाजपा नेता भी दिल्ली से लौटे थे। कौशिक, विधायक खजानदास के बाद दिल्ली गए पूर्व विधायक भी सीनियर नेताओं से मुलाकात कर देहरादून लौटे थे।

हर ब्लॉक में माडल तालाब बनाएं : केशव

» पात्रों को योजनाओं का लाभ मिले वरना होगी कार्रवाई

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

प्रयागराज। यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को निर्देशित किया कि गरीबों के हित में चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ पात्रों को मिले उसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। पात्र व्यक्ति लाभ पाने से वंचित रहे तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केशव मौर्य ने कहा कि योजनाओं में गड़बड़ी की शिकायत कहीं से नहीं मिलनी चाहिए। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायतों की सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को भी कहा।

निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधियों से पूछकर सड़कों के निर्माण की सूची बनाई जाए। विद्युत विभाग की समीक्षा में ट्रांसफार्मरों के बदलने में देरी की बात सामने आने पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी कि निर्धारित समय में खराब ट्रांसफार्मर बदले जाएं। उपभोक्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। लाइन लास रोकने को अभियान चलाकर कार्रवाई करने को निर्देशित किया। उपमुख्यमंत्री ने हर घर जल योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता का कार्यक्रम है। अमीर, गरीब, दलित, पिछड़े सभी को योजना से जोड़ा जाए। योजना की साप्ताहिक समीक्षा के लिए निर्देशित किया गया। हर घर तिरंगा कार्यक्रम की तैयारियों के बारे में जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री ने कहा, तिरंगे को मानक के अनुरूप बनाया जाए। इसमें स्वयं सहायता समूह की मदद लें। 15 अगस्त को जो अमृत सरोवर बन के तैयार हो गए हैं, वहां पर झंडा रोहण जरूर करें। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि आवास योजना के तहत अपात्रों को लाभांवित कराने वाले 34 ग्राम सचिवों, ग्राम विकास अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। उप मुख्यमंत्री ने अमृत सरोवर योजना के तहत ग्रामों में तालाब खोदाई कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रत्येक ब्लॉक में एक माडल तालाब जरूर बनाएं।

बालिकाओं की शिक्षा के सपनों को साकार करने के लिए सरकार कटिबद्ध : संदीप सिंह

» हर विकास खंड में होंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) को माध्यमिक स्तर कक्षा नौ से 12 तक की शिक्षा दिलाने के लिए उच्चीकृत किया जा रहा है, जिन विकासखंडों में केजीबीवी अभी संचालित नहीं है वहां भी सरकार नए विद्यालय खोलेगी। उच्चीकरण के बाद 377 विद्यालयों में अतिरिक्त 100 बालिकाओं के पठन-पाठन व आवासीय व्यवस्था के लिए एकेडमिक ब्लॉक व बालिका छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है।

इस वर्ष लगभग 200 भवनों का निर्माण पूर्ण होगा, जिसमें 20,000 बालिकाओं को लाभ मिलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कंवेंशन सेंटर लखनऊ में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत वार्डन की एक दिवसीय पुर्नबोधात्मक अभिमुखीकरण कार्यशाला में मंत्री ने कहा कि सरकार बालिकाओं की शिक्षा के सपनों को साकार करने के लिए कटिबद्ध है। केजीबीवी के 177 भवनों का निर्माण कार्य 2023-24 तक पूरा होगा, जिसमें 17700 अतिरिक्त बालिकाओं को लाभ मिलेगा। इसी तरह 2023-24 तक 446 केजीबीवी उच्चीकृत होने पर 1,18,600 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा सकेगा। सभी बालिकाओं को तकनीक से दक्ष किया जाए। उन्होंने कहा कि खान एकेडमी के प्रतिनिधि बालिकाओं को डिजिटल माध्यम से गणित सिखा रहे हैं। 2023-24 में हर बालिका को 25 घंटे तक खान एकेडमी पर अभ्यास करने के लक्ष्य को पूर्ण करने की कार्य योजना प्रस्तुत की। आईआईटी गांधीनगर गुजरात के प्रो. मनीष जैन ने केजीबीवी में संचालित जिज्ञासा कार्यक्रम के अनुभव बताया।

विवादों के बाद जल शक्ति विभाग में कार्यों को बंटवारा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। विवादों के बाद जल शक्ति विभाग के दोनों राज्यमंत्रियों दिनेश खटीक व रामकेश निषाद को कामों का बंटवारा कर दिया गया है। दिनेश खटीक ने इसी मुद्दे को लेकर इस्तीफा तक दे दिया था। अब दोनों राज्यमंत्रियों को बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत ड्रेनों का निरीक्षण, जलाशयों का निरीक्षण एवं समीक्षा, नहरों, बैराजों, लघु नहरों, परती भूमि का निरीक्षण आदि के काम दिए गए हैं। दोनों मंत्री बांध पुर्नस्थापना एवं सुधार परियोजना, बांध सुरक्षा एक्ट की समीक्षा, सहभागिता सिंचाई प्रबंधन एक्ट के अनुश्रवण का कार्य भी देखेंगे। इसके अलावा रामकेश निषाद राजस्व मंडल लखनऊ, प्रयागराज, आजमगढ़, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, वाराणसी, फैजाबाद एवं विंध्यांचल के सिविल यांत्रिक संगठन के राजस्व अधिष्ठान के समूह 'ग' के अपील एवं दंड से संबंधित कार्य देखेंगे। वहीं, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, झांसी, मिर्जापुर, बरेली मंडल के कार्य दिनेश खटीक को दिए गए हैं।

लोक सभा चुनाव की जंग को अखिलेश ने शुरू की किलेबंदी, संगठन को मजबूत करने में जुटे

» सदस्यता अभियान की संभाल रहे कमान, हर बूथ को मजबूत करने पर जोर

» अधिक से अधिक सदस्य बनाने की रणनीति पर काम कर रहे सपा प्रमुख

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। आगामी लोक सभा चुनाव के रण में उतरने से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सियासी किलेबंदी शुरू कर दी है। साथ ही संगठन को मजबूत करने में जुटे गए हैं। बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने के लिए वे खुद सदस्यता अभियान की निगरानी कर रहे हैं।

विधान सभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद सपा प्रमुख अब सधी रणनीति और सियासी चालें चल रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए उन्होंने संगठन और बूथ को मजबूत करने पर पूरा फोकस कर दिया है। इसके पहले सदस्यता अभियान संगठन के भरोसे रहता था किंतु इस बार खुद अखिलेश ने इसकी कमान संभाली है। उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं को अभियान की निगरानी के लिए जिला प्रभारी बना दिया है। इनमें पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री व संगठन के बड़े पदाधिकारी शामिल हैं। जिले में इनकी देखरेख में ही सदस्यता अभियान चलेगा। सदस्यता अभियान में इस बार 50 साधारण सदस्य बनाने के बाद बुकलेट जमा करने वाले को ही सक्रिय सदस्य बनाया जाएगा। पिछले वर्षों में ज्यादातर नेता अपने पास से पैसा जमा कर सक्रिय सदस्य बन जाते थे। अखिलेश ने इस प्रवृत्ति को कड़ाई से रोकने के प्रबंध किए हैं। प्रत्येक बूथ पर करीब 1200 मतदाता होते हैं, ऐसे में सपा प्रमुख ने हर एक बूथ पर अधिक से अधिक सपा सदस्य बनाने के लिए रणनीति बनाई है। इस साल के अंत में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं ऐसे में चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं को भी सदस्यता अभियान में लगाने की तैयारी है। इनके जरिये सपा अपने बूथ मजबूत करेगी। लोक सभा चुनाव में भी पार्टी उन वरिष्ठ नेताओं को तवज्जो देगी जो सदस्यता अभियान में बड़ी भूमिका निभाएंगे। सपा ऐसे नेताओं को टिकट में भी वरीयता दे सकती है।

पूर्व सांसद, विधायक व पूर्व मंत्रियों को सौंपी जिम्मेदारी

लखनऊ। सपा ने अपना सदस्यता अभियान तेज कर दिया है। पार्टी ने जिलेवार प्रभारी बना दिए हैं। इसमें विधायकों, पूर्व सांसद व पूर्व मंत्रियों के साथ वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। लखनऊ की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री अरविन्द सिंह गोप को सौंपी गई है। राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन को आगरा, श्याम लाल पाल व आलोक शाक्य को मैनपुरी, अक्षय यादव को फीरोजाबाद, असीम यादव को कासंगज, अमर सिंह यादव को हाथरस, राजाराम पाल को कानपुर नगर, नरेश उत्तम पटेल को कानपुर देहात, डा. नवल किशोर शाक्य व चंद्रपाल सिंह यादव को फर्रूखाबाद, अखिलेश कटियार व रामवृक्ष सिंह यादव को कन्नौज, विशम्भर प्रसाद निषाद को औरैया, आरएस कुशवाहा को झांसी, श्याम सुंदर यादव को ललितपुर और तिलक चन्द अहिरवार को जालौन की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं संतोष द्विवेदी व शिवशंकर पटेल को बांदा, विधायक विशंभर सिंह यादव को हमीरपुर, डा. चंद्रपाल सिंह यादव को महोबा, उदयवीर सिंह को चित्रकूट, धर्मेंद्र यादव को प्रयागराज गंगापार, कमलाकांत को प्रयागराज जमुनापार, डा. राजपाल कश्यप को फतेहपुर, इन्द्रजीत सरोज को कौशांबी व प्रतापगढ़ और सुरेंद्र सिंह पटेल व लाल बिहारी यादव को वाराणसी का प्रभारी बनाया गया है। हरदोई की जिम्मेदारी आरके चौधरी व रायबरेली की किरणमय नन्दा को सौंपी गई है। गोरखपुर में अम्बिका चौधरी व जफर अमीन को लगाया गया है।

एकमुश्त मुस्लिम वोटों पर नजर

सपा को विधान सभा चुनाव में नब्बे फीसदी मुस्लिम वोट मिले थे लेकिन सपा के सामने मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की चुनौती है। बसपा इसमें सेंध लगाने की तैयारी में है। कुछ हिस्सों में कांग्रेस भी इसकी दावेदार है। ऐसे में सपा के सामने अपने वोट बैंक को सहेजने की चुनौती है।

प्रदेश में बच्चों के तकनीकी ज्ञान को और मजबूत करेगी यूपी सरकार

» अब माध्यमिक स्कूलों में भी मिलेगा कौशल विकास का प्रशिक्षण

» नए उभर रहे क्षेत्रों में प्रशिक्षण कराने के लिए कर रहे प्रोत्साहित

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। सर्व शिक्षा अभियान को लेकर सरकार जागरूक है। हर बच्चा स्कूल जाए की नीति पर यूपी सरकार काम कर रही है। इसी क्रम में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा है कि अब स्कूल स्तर पर ही कौशल विकास प्रशिक्षण प्रारंभ करने की नीति बनाकर माध्यमिक शिक्षा विभाग से अनुबंध किया जा रहा है। प्रशिक्षण प्रदाताओं से अपील किया गया है कि वे अपने व्यावसायिक हितों से आगे बढ़कर सोचें और कौशल विकास मिशन की तरक्की में अधिकाधिक योगदान दें।

युवाओं को ड्रोन टेक्नोलाजी, सिविल एविऐशन, हास्पिटैलिटी व रिन्यूएबल एनर्जी जैसे नए उभर रहे क्षेत्रों में प्रशिक्षण कराने के लिए प्रोत्साहित करें। मंत्री अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन कार्यालय के सभागार में प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि शुरू से ही कौशल विकास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जोर देते आ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर हर घर झंडा कार्यक्रम में सभी से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए अनुरोध करते हुए कहा कि देश मुझे देता है सब कुछ, हम देश को क्या देंगे की भावना से कार्य करना चाहिए। प्रमुख सचिव सुभाष चंद शर्मा ने कहा कि कोरोना की वजह से कार्य की गति बाधित हुई, अब उनको नए जोश के साथ नए केंद्र बनाने व नए बैच बनाने पर ध्यान देना होगा। कौशल विकास मिशन के मिशन निदेशक आंद्रा वामसी ने कहा कि मिशन के कार्यों में जिलास्तर पर अधिक गुणवत्ता पाने के लिए मुख्य विकास अधिकारियों को ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रक्रियाओं का हिस्सा बनाया गया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला कौशल समिति की संस्तुतियों के आधार पर ही मुख्यालय से विभिन्न सेक्टरों में लक्ष्य का आवंटन किया जा रहा है। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिन संस्थाओं का परफारमेंस पिछले वित्तीय वर्ष में 40 प्रतिशत से कम हैं, उनको मिशन मुख्यालय से कोई लक्ष्य आवंटन नहीं किया गया है। प्रशिक्षण प्रदाताओं को ट्रेनिंग के बाद युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए प्रयास करें।

बेसिक शिक्षा विभाग की ट्रांसफर पॉलिसी जारी

उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन विभाग की तबादला नीति जारी हो गई है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक अब बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानांतरण की कार्यवाही ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण और नगर से नगर संवर्ग में ही होगी। इसके अलावा किसी भी आवश्यकता वाले स्कूल से शिक्षकों का स्थानांतरण या समायोजन नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के परिषदीय अध्यापकों का जिले के अंदर स्थानांतरण व समायोजन ऑनलाइन होगा। तबादला नीति के मुताबिक निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के आधार पर अधिक टीचर्स संख्या वाले स्कूल और अध्यापक की जरूरत वाले विद्यालय मानव संपदा पोर्टल पर 30 अप्रैल 2022 को उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर चिह्नित किया जाएगा। अध्यापक की जरूरत वाले विद्यालय का चिह्नित शिक्षकविहीन, एकल शिक्षक एवं ऐसे विद्यालय जहां से अधिक टीचर्स हैं लेकिन निशुल्क एवं बाल शिक्षा कानून के मानकों के अनुसार रिक्तियां हैं।

दो साल से कम सर्विस वालों का ट्रांसफर नहीं होगा

ऐसे अध्यापक या अध्यापिका जिनकी सेवा अवधि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख को दो वर्ष से कम होगी तो उन्हें समायोजन प्रक्रिया से अलग रखा जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे शिक्षक स्वेच्छा से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं अधिक अध्यापक वाले व शिक्षकों की जरूरत वाले विद्यालयों को चिन्हित करके वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और सबसे पहले सरप्लस शिक्षकों से 25 विद्यालयों का विकल्प लेकर तबादला किया जाएगा। जरूरत वाले ऐसे विद्यालय जहां के लिए एक ही आवेदन मिला है, उनका स्थानांतरण होगा।

10 दिन में खुलेगा ऑनलाइन पोर्टल

जिले के अंदर समायोजन व स्थानांतरण के लिए 10 दिन में एनआईसी के माध्यम से पोर्टल खोला जाएगा। शिक्षकों की कार्यरत विकासखंड में रिक्त न होने पर अन्य विकासखंड में भेजे जाएंगे। सरप्लस चिन्हित शिक्षकों को वरिष्ठता के आधार पर अवरोही क्रम में रखा जाएगा। ऐसे ही जिन विद्यालयों में शिक्षकों की जरूरत है उन्हें भी अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा, तब उनका समायोजन होगा।

जिद... सच की

Sanjay Sharma
editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

संसद में संवाद पर खामोशी

संसद के मानसून सत्र के दस दिन हंगामे की भेंट चढ़ गए। सत्ता-विपक्ष के बीच संवाद की जगह हो-हल्ला होता रहा। लिहाजा जरूरी विधेयक लटके हैं। लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में इस तरह की स्थिति बेहद चिंताजनक है। इसने साफ कर दिया कि आजादी के 75 साल बाद भी हम परिपक्व, जवाबदेह और जिम्मेदार नहीं बन सके हैं। सदन में न सत्ता पक्ष को सुना जा रहा है न विपक्ष को गंभीरता से लिया जा रहा है।

संसद के मानसून सत्र के दस दिन हंगामे की भेंट चढ़ गए। सत्ता-विपक्ष के बीच संवाद की जगह हो-हल्ला होता रहा। लिहाजा जरूरी विधेयक लटके हैं। लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में इस तरह की स्थिति बेहद चिंताजनक है। इसने साफ कर दिया कि आजादी के 75 साल बाद भी हम परिपक्व, जवाबदेह और जिम्मेदार नहीं बन सके हैं। सदन में न सत्ता पक्ष को सुना जा रहा है न विपक्ष को गंभीरता से लिया जा रहा है। दोनों सदनों में जनसरोकारों पर सार्थक बहस दूर-दूर तक दिखायी नहीं पड़ रही है। सवाल यह है कि संसद में हंगामे की संस्कृति क्यों हाबी हो गयी है? क्या सत्ता और विपक्ष दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं? क्या संसद को अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए विभिन्न सियासी दल इस्तेमाल कर रहे हैं? जनहित के मुद्दों और विधेयकों पर सार्थक संवाद क्यों नहीं हो रहे हैं? जनता के खून-पसीने की कमाई को हंगामे में क्यों उड़ाया जा रहा है? क्या ऐसे ही हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने का दावा कर सकते हैं? क्या सदन में संवाद बनाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की नहीं है? क्या ये गतिविधि दुनिया में गलत संदेश नहीं भेज रही है?

लोकतंत्र में विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने और जनहित के मुद्दों पर घेरने का पूरा अधिकार है। पहले भी कई मुद्दों पर संसद में हंगामे हुए लेकिन वे लगातार नहीं चलते थे। यह स्थिति कुछ वर्षों से पूरी तरह बदल गई है। हंगामे से संसदीय कार्यवाही को बाधित करने का नया चलन शुरू हुआ है। संसद के मानसून सत्र के दौरान भी यही दिखा। कभी सत्ता तो कभी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही ठप रही। महंगाई और जीएसटी लगाने का विरोध कर रहे विपक्ष न सरकार को सुन रहे हैं और न सरकार इन्हें गंभीरता से ले रही है। सत्ता और विपक्ष जनसरोकारों की जगह अपने राजनीतिक निहितार्थों को अधिक अहमियत देते दिख रहे हैं। टकराव की यह स्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। सत्ता और विपक्ष को सदन की कार्यवाही में देश के सरोकारों को प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर संसद में इसलिए भेजती है ताकि वे जनहित में कानून बनाएं और लोगों को राहत मिल सके। सदन की कार्यवाही में जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। एक दिन की कार्यवाही में छह करोड़ का खर्च आता है। हैरानी यह है कि संसद में जारी गतिरोध को टालने की गंभीर कोशिश नहीं की जा रही है। इसमें दो राय नहीं कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले इसके लिए सत्ता पक्ष सबसे अधिक जिम्मेदार है लेकिन विपक्ष को भी अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो संसद की गरिमा तार-तार हो जाएगी।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

देश में रेवड़ी कल्चर खतरनाक

ललित गर्ग

मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वाली राजनीति देश के विकास की एक बड़ी बाधा है। जो नेता इसे परोपकार मानते हैं वे देश की जनता को गुमराह करते हैं। यह सरासर प्रलोभन एवं चुनावों में अपनी जीत को सुनिश्चित करने का हथियार है। जीत के लिए जनता से मुफ्त सामान का वादा, राज्य के खजाने पर भारी आर्थिक असंतुलन का कारण है। अब इस मुफ्त संस्कृति एवं रेवड़ियां बांटने के राजनीतिक प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार से स्पष्ट करने को कहा है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियों की ओर से मुफ्त में चीजें बांटने या ऐसा करने का वादा करने को वह कोई गंभीर मुद्दा मानती है या नहीं? अदालत ने केंद्र को वित्त आयोग से यह भी पता लगाने को कहा कि पहले से कर्ज में डूबे राज्य में मुफ्त की योजनाओं पर अमल रोका जा सकता है या नहीं?

लोकतंत्र में यह मुफ्त बांटने की मानसिकता एक तरह का राजशाही का अंदाज ही कहा जायेगा जो लोकतंत्र के मूल्यों के विपरीत है। लोकतंत्र में कोई भी सरकार आम जनता की सरकार होती है और सरकारी खजाने में जो भी धन जमा होता है वह जनता से वसूले गये शुल्क या टैक्स अथवा राजस्व का होता है। राजशाही के विपरीत लोकतन्त्र में जनता के पास ही उसके एक वोट की ताकत के भरोसे सरकार बनाने की चाबी रहती है। दरअसल, जनता के हाथ की इस चाबी को अपने पक्ष में घुमाने एवं जीत का ताला खोलने के लिये यह मुफ्त की संस्कृति एक राजनीतिक विकृति के रूप में विकसित हो रही है। चुनावों में सत्ता हासिल करने के लिए अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों की ओर से किए जाने वाले वादे की शक्ल अब बीते कुछ समय से कोई चीजें या सुविधाएं मुफ्त मुहैया कराने के रूप में सामने आने लगी है अगर एक पार्टी विद्यार्थियों को मुफ्त लैपटाप, वृद्धों को मुफ्त धार्मिक यात्रा, महिलाओं को मुफ्त बस सफर देने का वादा करती है तो दूसरी पार्टियां बिजली-पानी और स्कूटी या गैस सिलेंडर। हालत यह हो गई है कि इस मामले में लगभग सभी पार्टियों के बीच एक होड़ लग गई है। इससे राज्यों का आर्थिक संतुलन लड़खड़ाता है या वे कर्ज में डूबते हैं तो इसकी चिन्ता किसी भी दल की सरकार को नहीं है।

अक्सर विकास से संबंधित किसी काम के समय पर पूरा नहीं होने को लेकर सरकारें कोष में धन की कमी और कर्ज के बोझ का रोना रोती हैं लेकिन वहीं वे मुफ्त में लोगों को कोई सामान बांटने से लेकर बिजली या पानी

जैसी योजनाएं चला कर जनपक्षीय होने का दावा करते हुए राज्य के आर्थिक बजट को डांवाडोल कर देती हैं। ऐसे में चुनावों के दौरान दलों की ओर से ऐसे वादे किए जाने पर पूरी तरह रोक लगाना लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा के लिये जरूरी है। लोगों द्वारा चुने गये प्रतिनिधि जनता के 'मालिक' नहीं बल्कि 'नौकर' होते हैं और केवल पांच साल के लिए जनता उन्हें देश या प्रदेश की सम्पत्ति या खजाने का रखरखाव (केयर टेकर) करने के लिए चुनती है लेकिन राजनीति में घर कर रही विकृतियों, चरमराते राजनीतिक मूल्यों एवं येन-केन-प्रकारेण चुनाव जीतने की होड़ के चलते जन-प्रतिनिधि स्वयं को मालिक मानने लगे हैं। चुनावों से पहले ही मुफ्त सौगात देने के वादे करके राजनीतिज्ञ या राजनीतिक दल जनता के खजाने को निजी सम्पत्ति समझ कर मनचाही सौगात बांटने की जो घोषणा करते हैं, वह पूरी तरह लोकतन्त्र को आधिकारिक रिश्वतखोरी के तंत्र में बदलने का घिनौना एवं विरोधाभासी प्रयास है। सवाल है कि हर छोटी-मोटी सुविधाओं या आर्थिक व्यवहार को 'कर' के दायरे में लाने और उसे सख्ती से वसूलने वाली सरकारें इतने बड़े पैमाने पर कोई चीज कैसे मुफ्त देने लगती हैं? यह जनता को गुमराह करने का जरिया है। इसका एक अन्य पहलू यह है कि कुछ सुविधाएं या सेवाएं मुफ्त किए जाने से इतर सरकार क्या जनता से अन्य मदों में कर नहीं वसूलती है? फिर विशेष या आपात स्थिति में अगर जीवन-निर्वाह के लिए लोगों को कोई सामान नि:शुल्क दिया जाता है तो क्या वह सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है? एक आदर्श सरकार वही है जो अपनी जनता में मुफ्तखोरी में जीने की आदत डालने की बजाय उसे कर्ममय एवं उद्यमी बनाये। उन्हें रोजगार दें, काम-धंधों में लिप्त करें। जितनी राशि मुफ्त में सुविधाएं या चीजें देने में खर्च होती है, वही राशि यदि उद्यम एवं विकास में खर्च की जाये तो प्रांत का विकास होगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, समृद्धि का वातावरण बनेगा। मुफ्त की संस्कृति एवं प्रचलन पर नियंत्रण जरूरी है, इसके लिये वित्त आयोग आवंटन के समय किसी राज्य सरकार का कर्ज और मुफ्त में सामान मुहैया कराने की कीमत को देख कर अपना निर्णय ले सकता है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए देश राजनीति की इस विकृति से मुक्त हो, यह अपेक्षित है।

बाघों को सुरक्षित करना जरूरी

ज्ञानेंद्र रावत

केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कुछ दिन पहले संसद में बताया कि 2019 से 2021 के बीच हर तीसरे दिन एक बाघ की मौत हुई है। इन तीन सालों में कुल 329 बाघ मौत के मुंह में चले गये। इनमें 68 की मौत स्वाभाविक हुई, पांच की अस्वाभाविक। 29 शिकारियों द्वारा मारे गये और 30 की मौत लोगों के हमले में हुई। ये आंकड़े इस बात का सबूत हैं कि बाघों के संरक्षण की दिशा में किये जा रहे सरकारी प्रयास बेमानी हैं।

इस साल के शुरू में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषणा की थी कि राजस्थान के रणथंभौर से लेकर मध्य प्रदेश के पन्ना तक वन्यजीव गलियारा बनाया जायेगा। इसका मुख्य कारण अभयारण्यों में क्षमता से बहुत अधिक बाघों का होना है और इससे भोजन, क्षेत्र और आवास की समस्या के चलते मानव आबादी में हमले की आशंका बढ़ गयी है। वर्ष 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। उसके बाद बाघ बचाओ परियोजनाओं की शुरुआत हुई। वर्तमान में देश में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं। दुनिया के 71 फीसदी, यानी लगभग 3000 बाघ हमारे देश में हैं। देश में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड में हैं। उत्तराखंड में कार्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक बाघ हैं, जबकि छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों में इनकी आबादी कम है। इस साल सरकार ने इन राज्यों के कुछ अभयारण्यों को टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है। उत्तराखंड में अब बाघ खुद नये गलियारे बना रहे हैं। कार्बेट-नघौर के बाघ इसके सबूत हैं। यहां हैडाखान के अलावा पिथौरागढ़ के अस्कोट व केदारनाथ में भी बाघों की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, बौरवैली से देचौरी रेंज होते हुए नैनीताल शहर से लगे पंगूट के जंगलों तक, दाबका वैली से नैनीताल के विनायक तक और मोहान कुमखेत से बेताल घाट व अल्मोड़ा के जंगलों तक अब बाघ पहुंच रहे हैं। कार्बेट-नघौर में बाघों की तादाद तेजी से बढ़ी है इसलिए वे नये इलाकों की तलाश में पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं।

जंगलों के अंधाधुंध कटान ने इसमें अहम भूमिका निभायी है। अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल टाइगर फोरम की मानें तो भारत की स्थितियां बाघों के आवास के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। भारत में 38,915 वर्ग किलोमीटर इलाका बाघों के रहने लायक है। नेपाल और तिब्बत भी बाघों के लिए उपयुक्त हैं। भारत, नेपाल और भूटान के अधिक ऊंचाई वाले पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन में इन देशों में करीब 52,671 वर्ग किलोमीटर इलाका बाघों के अनुकूल पाया गया है। इसके बावजूद बाघ मर रहे हैं, यह चिंताजनक स्थिति है। नौ साल पहले रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 13 देशों ने 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस लक्ष्य को भारत ने चार साल पहले ही हासिल कर लिया था। इससे ग्लोबल टाइगर फोरम के अध्ययन के निष्कर्ष की पुष्टि होती है कि भारत बाघों के लिए सर्वोत्तम सुरक्षित स्थल है। विडंबना यह है कि हमारे यहां जहां बाघों की तादाद में बढ़ोतरी के दावे किये जा रहे हैं, इसका कारण वन्यजीव अभयारण्यों के बेहतर प्रबंधन को माना जा रहा है, वहीं देश में बाघों की मौतों में बढ़ोतरी होना बेहद चिंताजनक बात है।

भले सरकार द्वारा बाघ संरक्षण की दिशा में ढेर सारी योजनाएं चलायी जाएं मगर असलियत में देश में बाघों के शिकार की गति बढ़ रही है। वर्ष 2012 से हर साल औसतन 98 बाघ की मौत हुई है। सबसे ज्यादा मौतें 2021 में हुईं। जब यह संख्या 126 रही थी। इनमें 60 अवैध शिकार, सड़क हादसों व इंसानी संघर्ष में मरे थे। इनमें 44 मध्य प्रदेश, 26 महाराष्ट्र और 14 कर्नाटक में मरे थे। बीते आठ सालों में 750 बाघों की मौत हुई जिनमें 168 की शिकार से और 319 प्राकृतिक कारणों से मरे। बाघों के आपसी संघर्षों में होने वाली मौतों की संख्या बढ़ना भी चिंता की बात है। बीते कुछ सालों में 350 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के वन्यजीव उत्पादों के बरामद होने से यह साबित होता है कि वन्यजीव तस्करों को कोई भय नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, बाघों के प्राकृतिक आवासों का संरक्षण बहुत जरूरी हो गया है। सरकार बीते दस सालों में 530 से अधिक बाघों की मौत का दावा करती है जबकि वन्य जीव विशेषज्ञ मौतों की संख्या इससे कहीं अधिक बताते हैं। इनके आवास स्थल जंगलों में अतिक्रमण, प्रशासनिक कुप्रबंधन, चारागाह का सिमटते जाना, जंगलों में प्राकृतिक जलस्रोत तालाब, झीलों के खात्मे से इनका मानव आबादी की ओर आना जैसी कई समस्याएं हमारे सामने हैं। ऐसे में इन वजहों तथा आपसी संघर्ष और बढ़ते अवैध शिकार के चलते बाघों की मौतों का आंकड़ा हर साल बढ़ता ही जा रहा है। पिछले साल राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की सदस्य एवं सांसद दीया कुमारी ने आरोप लगाया था कि रणथंभौर अभयारण्य से 26 बाघ गायब हो गये। दुखद यह है कि प्रशासन इस बाबत चुप्पी साधे रहा। यह विचारणीय है कि जब वन्यजीव अभयारण्यों का प्रबंधन इतना बढ़िया है, उस हालत में बाघ कैसे गायब हो जाते हैं या शिकारियों द्वारा मार दिये जाते हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है।

दूध को बच्चों से लेकर बड़े-बूढ़ों तक के लिए आवश्यक माना गया है। इसमें मौजूद कैल्शियम सिर्फ हड्डियों को ही मजबूती प्रदान नहीं करता है। बल्कि इससे अन्य भी कई फायदे मिलते हैं। हालांकि यह देखने में आता है कि अधिकतर घरों में लोग दूध पीना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि उन्हें इसका स्वाद बोरिंग लगता है। ऐसे में दूध में फ्लेवर एड करके उसे और भी अधिक डिलिशियस बनाया जा सकता है। अमूमन लोग दूध को टेस्टी बनाने के लिए मार्केट में मिलने वाले तरह-तरह के फ्लेवर या सिरप एड करते हैं। जबकि अगर आप चाहें तो इसकी जगह अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक ऐसा मसाला है, जिसकी महक और स्वाद तो बेमिसाल होता ही है। साथ ही इससे सेहत को भी कई लाभ मिलते हैं। अदरक में एंटी-इन्फ्लमेट्री प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको अदरक के दूध से मिलने वाले कुछ बेमिसाल फायदों के बारे में बता रहे हैं।

अदरक का दूध

पीने से सेहत को मिलते हैं कई लाभ

प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए मजबूत

शरीर के स्वस्थ रहने की कुंजी है। प्रतिरक्षा तंत्र का मजबूत होना। यह शरीर के लिए एक शील्ड की तरह काम करता है और व्यक्ति को कई तरह की बीमारियों से बचाता है। इम्युन सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए अदरक के दूध का सेवन अवश्य किया जाना चाहिए। अदरक का दूध प्रतिरक्षा प्रणाली पर सकारात्मक प्रभाव छो?कर शरीर से हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। अदरक के दूध में एंटीऑक्सिडेंट होते हैं जो हमें इंटरनल फ्री रेडिकल्स से बचा सकते हैं। नतीजतन, यह आपको सुरक्षित और स्वस्थ रखता है।

ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना करे कम

जब व्यक्ति की उम्र बढ़ने लगती है, तो उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। लेकिन, अदरक का दूध पीने से आपकी हड्डियों की मजबूती प्राकृतिक रूप से बढ़ाई जा सकती है। दूध हड्डियों की कमजोरी को दूर करने में मदद करता है क्योंकि इसमें कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। वहीं, अगर दूध में अदरक को भी शामिल कर लिया जाए तो इससे आपकी हड्डियों को अतिरिक्त शक्ति मिलती हैं और संक्रमण व सूजन आदि से बचाव होता है। 40 की उम्र के बाद नियमित रूप से अदरक का दूध पीने से ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

पाचन शक्ति को बनाए बेहतर

अदरक को पाचन तंत्र के लिए काफी अच्छा माना गया है। यह एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, पेट दर्द और कब्ज जैसी चीजों से बचाता है। अगर आप अपनी डाइट में अदरक के दूध को शामिल करते हैं तो इससे कई तरह की पाचन संबंधी समस्याओं से आसानी से बचा जा सकता है।

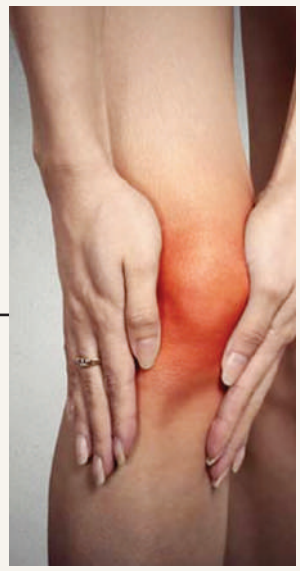

दर्द से मिलती है राहत

बहुत लंबे समय से, सूजन को कम करने के लिए अदरक का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता रहा है। कई अध्ययन में यह बात सामने आई है कि घुटने के पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस के दर्द को यह कम करने की क्षमता रखता है। वहीं अदरक की चाय सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, मासिक धर्म में ऐंठन और अन्य प्रकार के दर्द को कम करने में मदद कर सकती है। लेकिन अगर अदरक का दूध पिया जाए तो इससे आपको अतिरिक्त लाभ मिल सकता है।

गले की खराश से मिलता है आराम

यदि आप इन दिनों गले में खराश की समस्या से परेशान हैं, तो अदरक का दूध यकीनन आपको काफी राहत दिलाएगा। सर्दी, फ्लू और खांसी से अक्सर गले में संक्रमण हो जाता है, जिससे गले में दर्द होता है और आपके लिए बात करना, खाना या पीना काफी मुश्किल हो जाता है। एक गिलास अदरक का दूध पीने के बाद आप बेहतर महसूस करेंगे क्योंकि इसमें सूजन-रोधी गुण होते हैं। तो अब आप भी अदरक के दूध को अपनी डाइट में शामिल करें और खुद को अधिक हेल्दी बनाएं।

हंसना मना है

टीचर- इंसान वो है जो हमेशा दूसरों की मदद करे। स्टूडेंट- लेकिन एग्जाम के समय ना तो आप खुद इंसान बनती हो और ना ही दूसरों को बनने देती हो।

मेरा एक दोस्त मुझसे हमेशा कहता था. भाई कुछ अलग कर, मैंने उसकी गर्लफ्रेंड को उससे अलग करवा दिया, अब जूते लेकर मुझे ढूढ़ रहा है।

पति- तुमने तो सुबह कहा था कि रात के खाने में दो ऑप्शन होंगे यहां तो एक ही सब्जी दिख रही है? पत्नी- ऑप्शन अभी भी दो हैं। पति- वो कैसे? पत्नी- खाना है तो खाओ, नहीं तो रहने दो।

लड़का, लड़की देखने गया, उन्हें बात करने के लिए अकेले बिठा दिया गया। लड़की ने डरते हुए पूछा। भैया आप कितने भाई बहन हैं? लड़का- अभी तक तो तीन ही थे...अब चार हो गए।

राजू और मोहन दोनों भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे। अध्यापिका- तुम दोनों ने अपने पापा का नाम अलग-अलग क्यों लिखा? राजू- मैडम फिर आप कहोगे कि नकल मारी है, इसीलिए।

कहानी

कौवे और उल्लू का बैर

एक बार हंस, तोता, बगुला, कोयल, कबूतर, उल्लू आदि सब पक्षियों ने सभा करके यह सलाह की कि उनका राजा वैनतेय केवल वासुदेव की भक्ति में लगा रहता है। व्याधों से उनकी रक्षा का कोई उपाय नहीं करता; इसलिये पक्षियों का कोई अन्य राजा चुन लिया जाये। कई दिनों की बैठक के बाद सब ने एक सम्मति से सर्वांग सुंदर उल्लू को राजा चुना। अभिषेक की तैयारियां होने लगीं, विविध तीर्थों से पवित्र जल मंगाया गया, सिंहासन पर रत्न जड़े गए, स्वर्णघट भरे गए, मंगल पाठ शुरू हो गया, ब्राह्मणों ने वेद पाठ शुरू कर दिया, नर्तकियों ने नृत्य की तैयारी कर लीं; उलूकराज राज्यसिंहासन पर बैठने ही वाले थे कि कहीं से एक कौवा आ गया। कौवे ने सोचा यह समारोह कैसा? यह उत्सव किस लिए? पक्षियों ने भी कौवे को देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। उसे तो किसी ने बुलाया ही नहीं था। फिर भी, उन्होंने सुन रखा था कि कौआ सब से चतुर कूटराजनीतिज्ञ पक्षी है; इसलिये उस से मन्त्रणा करने के लिये सब पक्षी उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। उलूक राज के राज्याभिषेक की बात सुन कर कौवे ने हंसते हुए कहा-यह चुनाव ठीक नहीं हुआ। मोर, हंस, कोयल, सारस, चक्रवाक, शुक आदि सुन्दर पक्षियों के रहते दिवान्ध उल्लू ओर टेढ़ी नाक वाले अप्रियदर्शी पक्षी को राजा बनाना उचित नहीं है। वह स्वभाव से ही रौद्र है और कटुभाषी है। फिर अभी तो वैनतेय राजा बैठा है। एक राजा के रहते दूसरे को राज्यासन देना विनाशक है। पृथ्वी पर एक ही सूर्य होता है; वही अपनी आभा से सारे संसार को प्रकाशित कर देता है। एक से अधिक सूर्य होने पर प्रलय हो जाती है। प्रलय में बहुत से सूर्य निकल जाते हैं; उन से संसार में विपत्ति ही आती है, कल्याण नहीं होता। राजा एक ही होता है। उसके नाम-कीर्तन से ही काम बन जाते हैं। यदि तुम उल्लू जैसे नीच, आलसी, कायर, व्यसनी और पीठ पीछे कटुभाषी पक्षी को राजा बनाओगे तो नष्ट हो जाओगे। कौवे की बात सुनकर सब पक्षी उल्लू को राज-मुकुट पहनाये बिना चले गये। केवल अभिषेक की प्रतीक्षा करता हुआ उल्लू उसकी मित्र कृकालिका और कौवा रह गये। उल्लू ने पूछा-मेरा अभिषेक क्यों नहीं हुआ? कृकालिका ने कहा-मित्र! एक कौवे ने आकर रंग में भंग कर दिया। शेष सब पक्षी उड़कर चले गये हैं, केवल वह कौवा ही यहाँ बैठा है। तब उल्लू ने कौवे से कहा-दुष्ट कौवे! मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे कार्य में विघ्न डाल दिया। आज से मेरा तेरा वंशपरंपरागत वैर रहेगा। यह कहकर उल्लू वहां से चला गया। कौवा बहुत चिन्तित हुआ वहीं बैठा रहा। उसने सोचा-मैंने अकारण ही उल्लू से वैर मोल ले लिया। दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप करना और कटु सत्य कहना भी दु:खप्रद होता है। यही सोचता-सोचता वह कौवा वहां से चला गया। तभी से कौओं और उल्लुओं में स्वाभाविक वैर चला आता है।

7 अंतर खोजें

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष

यह अवधि मिश्रित प्रभाव प्रदान करती है। आपके पास नए अवसर होंगे और उनका उपयोग करके लाभ प्राप्त करेंगे। व्यावसायिक एवं आर्थिक लाभ संभव है।

वृषभ

आज का दिन आपके लिये बहुत से नये पल लेकर आया है। आपको करियर के मामले में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आपके आस-पास का माहौल अच्छा बना रहेगा।

मिथुन

किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आपको और अधिक ध्यान लगाने की जरुरत हो सकती है। व्यापार में बढ़ोतरी होगी। ऑफिस में वेतन वृद्धि हो सकती है।

कर्क

आज आपको बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं। किन्तु यदि आप आर्थिक लाभ हेतु आसान तरीकों की तलाश करते हैं तो आप केवल बुरे परिवर्तनों को आमंत्रित कर रहे हैं।

सिंह

आज आप किसी काम में बहुत ज्यादा ही बिजी रह सकते हैं। नजदीकी रिश्तों में किसी बात से खटास आ सकती है। आपको सबके साथ प्रेम-भाव बनाकर रखना चाहिए।

कन्या

आज आपका भाग्य आपके साथ है, इसलिए जीतने का अच्छा मौका आपके पास रहेगा। आप नए संकल्प कर सकते है। आपके सभी विकल्प सही साबित हो सकते है।

तुला

कार्य स्थल पर सकारात्मक और सहायक विकास होगा। आप लाभ के लिए तत्पर हैं। यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं, तो आप अपने प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे।

वृश्चिक

आज आपका दिन सामान्य से अच्छा रहने वाला है। आप लोगों की बातों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अपने काम की रूपरेखा में बदलाव कर सकते हैं।

धनु

आज आपको नए संपर्कों का आज लाभ मिल सकता है। लोगों को दिए पुराने कर्ज वापिस मिल सकते हैं या फिर किसी नयी परियोजना पर लगाने के लिए धन अर्जित कर सकते हैं।

मकर

आज ईमानदारी से किया गया कार्य अतिरिक्त लाभ के रूप में अपने फल देगा। व्यक्तिगत जीवन को अपने व्यावसायिक हितों के साथ हस्तक्षेप न करने दें।

कुम्भ

आज का दिन आपके लिये कुछ अच्छे पल लेकर आया है। आप अपनी मेहनत और क्षमता के बल पर सफलता हासिल करेंगे। आपके सारे काम मन-मुताबिक पूरे होंगे।

मीन

खरीदारी सम्बन्धी किसी ऑफर या लाटरी खरीदने का जोखिम उठा सकते हैं। कुछ बड़ी दिक्कत का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। अपनी क्षमता पर आपको ध्यान रखना होगा।

बॉलीवुड | मन की बात

कोई भी फिल्म-इवेंट और ऐड हो, पैसों के लिए मैं मना नहीं करता : अक्षय

अक्षय कुमार इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म रक्षा बंधन के प्रमोशन में बिजी चल रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान एक्टर ने कहा कि उन्होंने कभी काम को न नहीं बोला, चाहे वो कोई फिल्म हो या इवेंट या फिर एड हो। साथ ही उन्होंने कहा कि वो पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उस पैसे को वो समाज के लिए अच्छे कामों में यूज करना चाहते हैं। अक्षय ने कहा कि मुझसे लोग पूछते हैं कि आप एक साल में इतनी फिल्में क्यों करते हैं? लेकिन मैंने अपनी लाइफ में तीन चीजें सीखी हैं- काम, कमाई और कर्म। मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए जितना हार्ड वर्क कर सकता हूं करता हूं। जो भी काम मेरे पास आता है, मैं कभी मना नहीं करता। कैसा भी रोल हो, कोई भी फंक्शन हो, किसी भी चीज का एड करना हो। अक्षय ने आगे कहा क्योंकि काम से आती है कमाई और उससे मैं कोशिश करता हूं अच्छे कर्म करने की। इसलिए आप जितना काम करोगे, उतना कमाओगे और उससे ज्यादा आप सोसाइटी को वापस कर देते हो। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। अक्षय अपनी अगली फिल्म रक्षा बंधन में भूमि पेडनेकर के साथ नजर आएंगे। यह फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होगी। इस फिल्म को आनंद एल राय ने डायरेक्ट किया है और हिमांशु शर्मा और कनिका ढिल्लो ने लिखा है। अक्षय के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उनके पास फिल्म सेल्फी है। यह फिल्म 24 फरवरी 2023 को रिलीज होगी। अक्षय के अलावा कॉमेडी ड्रामा फिल्म में इमरान हाशमी, डायना पेंटी और नुसरत भरूचा भी लीड रोल में हैं। अक्षय, राधिका मदान के साथ सूराराई पोतरु के हिंदी रीमेक में नजर आएंगे।

शमशेरा के फ्लॉप होने पर छलका संजय दत्त का दर्द, बोले

यह खून, पसीने और आंसुओं से बनी थी

करण मल्होत्रा के निर्देशन में बनी 'शमशेरा'22 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 150 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर, वाणी कपूर, संजय दत्त लीड रोल में देखे गए। फिल्म में भले ही इन सभी सितारों ने दमदार एक्टिंग की लेकिन यह दर्शकों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना पाई और इस तरह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अब फिल्म की असफलता को लेकर संजय दत्त ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक इमोशनल स्टेटमेंट शेयर किया है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में उन सारी बातों का जिक्र किया है, जिसे उन्होंने बीते कुछ दिनों में फील किया है।

आपको बता दें कि संजय दत्त से पहले फिल्म के डायरेक्टर करण मल्होत्रा ने भी अपने सोशल अकाउं पर 'शमशेरा' के फ्लॉप होने पर अफसोस जताता था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था, 'मेरे प्यारे शमशेरा, आप जैसे हैं वैसे ही प्रभावशाली हैं। मेरे लिए इस मंच पर खुद को व्यक्त करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां वह जगह है जहां आपके लिए प्यार, नफरत, उत्सव और अपमान मौजूद है।' उन्होंने आगे ये भी लिखा था, 'हर चीज का एक साथ सामना करेंगे, अच्छा बुरा और बदसूरत, शमशेरा परिवार, शमशेरा के कलाकारों और चालक दल के लिए ये शोर शराबा। प्यार, आशीर्वाद और चिंता जो हम पर बरस रही है, वह है सबसे कीमती और कोई भी इसे हमसे दूर नहीं ले सकता। करण मल्होत्रा के बाद अब संजय दत्त ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर शेयर किया है। उनके पोस्ट में उनका दर्द साफ झलक रहा है। संयज दत्त अपने पोस्ट में लिखा- शमशेरा प्यार का एक ऐसा मेहनत है, जिसे हमने अपना सब कुछ दिया है। यह खून, पसीने और आंसुओं से बनी है, यह एक सपना है, जिसे हम स्क्रीन पर लेकर आए। दर्शकों के मनोरंजन के लिए फिल्में बनाई जाती हैं। संजय दत्त अपने पोस्ट की आखिरी में फिल्म शमशेरा की कास्ट और क्रू को धन्यवाद देते हुए डायरेक्ट के प्रति अपनी फीलिंग शेयर किया है।

अनन्या और देवराकोंडा ने मुंबई के लोकल ट्रेन में किया सफर

विजय देवरकोंडा-अनन्या पांडे इन दिनों अपनी फिल्म लाइगर को लेकर छाए हुए हैं। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसे फैंस ने खूब पसंद भी किया है। वहीं अब अनन्या और विजय देवरकोंडा जोर-शोर से फिल्म के प्रमोशन में जुट हुए हैं। हाल ही में दोनों स्टार्स मुंबई लोकल में भी सफर करते हुए दिखाई दिए। फिल्म के प्रमोशन के लिए दोनों ने मुंबई के खार स्टेशन से लोअर परेल तक का सफर तय किया। साथ ही आज इस फिल्म का दूसरा गाना वाट लगा देंगे भी रिलीज कर दिया है। बता दें कि विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की लाइगर 25 अगस्त 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। विजय देवरकोंडा इन दिनों अपनी फिल्म लाइगर को लेकर छाए हुए हैं। फिल्म का दूसरा गाना वाट लगा देंगे आज रिलीज हो गया है। इस गाने को विजय ने ही गाया है। गाने में विजय की जर्नी दिखाई है कि कैसे वह स्ट्रीट फाइटर से देश के लिए फाइट करने जाता है। गाने में बॉक्सिंग रिंग में विजय देवरकोंडा पूरे जोश के साथ नजर आ रहे हैं। गाने की लिरिक्स फिल्म के डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने लिखे हैं और कंपोज सुनील कश्यप ने किया है।

अजब-गजब | यहां की परंपरा जानकर रह जाएंगे हैरान!

यहां परंपरा के नाम पर काट दी जाती है महिलाओं के हाथों की अंगुलियां

दुनियाभर में अलग अलग रीति रिवाज हैं, जिन्हें लोग सदियों से निभाते आ रहे हैं। इनमें से कुछ रीति रिवाज बड़े अजीबोगरीब और विचित्र हैं। ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब और विचित्र परंपराएं पापुआ न्यू गिनी नाम के एक देश में निभाई जाती हैं। दरअसल, यहां पर दानी नाम की जनजाति के लोग रहते हैं। इस जनजाति में सदियों से इस तरह की परंपराएं निभाई जाती रही हैं। दानी नाम की जानजाति के लोग बेहद निर्दयी और दर्दनीय रीति-रिवाजों को निभाती हैं। यहां रीति रिवाजों के नाम पर महिलाओं के साथ अन्याय होता है। उनको असहनीय दर्द दिया जाता है। यहां के लोगों की परंपरा के अनुसार घर के मुखिया की मौत की सजा महिलाओं को जिंदगी भर भुगतनी पड़ती है।

पापुआ न्यू गिनी द्वीप पर रहने वाली दानी जनजाति के लोग दुनिया की सबसे दर्दनाक और क्रूर परंपरा निभाने के लिए मशहूर हैं। इस परंपरा के अनुसार दानी जनजाति में परिवार के मुखिया की मौत का शोक जताने के लिए परिवार की महिलाओ के दोनों हाथों की कुछ अंगुलियां काट दी जाती है। यहां के लोगों के अनुसार ये दर्दनाक होता है, लेकिन इससे मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है, लेकिन इस दौरान महिलाओं के साथ जो होता है वो रूह कंपा देने वाला होता है। अंगुली काटने से पहले महिलाओं की अंगुलियों को रस्सी से बांध दिया जाता था, ताकि खून का प्रवाह रुक जाए। उसके बाद कुल्हाड़ी से उनकी अंगुलियों को काटा जाता था। ये दर्दनाक काम सिर्फ परिवार की महिलाओं को ही करना पड़ता था। हालांकि अब सरकार ने इस परंपरा को बंद करा दिया है।

देश में क्यों छापा गया जीरो रुपये का नोट, क्या है इसकी पूरी कहानी

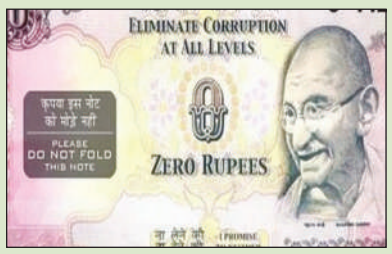

आपने 1 रुपये से लेकर 2 हजार रुपये तक के नोट को देखा होगा। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा छापे जाने वाले इन नोटों का इस्तेमाल हम सभी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। लेकिन हम आपको एक ऐसे नोट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे। क्या आपको पता है कि देश में जीरो रुपये का नोट भी छपा था? जीरो रुपये के नोट पर भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर छापी गई है। यह बिल्कुल दूसरे नोटों की तरह दिखाई देता है। लेकिन अब आपके मन में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि आखिर जीरो रुपये के नोट क्यों छापे गए। इस नोट का होता क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन नोटों को नहीं छापा था। इस नोट को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम के तहत छापा गया था। इस जीरो रुपये के नोट को छापने का आईडिया दक्षिण भारत की एक हत्रह का था। साल 2007 में भ्रष्टाचार के खिलाफ इस नोट को हथियार के रूप में शुरू किया गया था। तमिलनाडु में काम करने वाली इस एनजीओ ने करीब 5 लाख जीरो रुपये के नोट छापे थे। इन नोटों को हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम चार भाषाओं में छापा गया था जिसे लोगों में बांट दिया गया। इस नोट पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कई मैसेज लिखे थे। इन नोट पर लिखा था, भ्रष्टाचार खत्म करो, अगर कोई घूस मांगता है, तो इस नोट को दें और मामले के बारे में हमको बताएं। ना लेने की और ना देने की कसम खाते हैं। इस नोट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और नोट पर नीचे एनजीओ का फोन नंबर और ईमेल आईडी दी गई थी। एनजीओ ही इस जीरो रुपये के नोट को बनाती थी और रिश्वत मांगने वाले लोगों को देती थी। जीरो रुपये का नोट भ्रष्टाचार के खिलाफ एक प्रतीक था।

विकास के मोर्चे पर सरकार फेल आंकड़े खोल रहे पोल : अखिलेश

» नकली विकास की खुल रहीं परतें, भ्रमित कर रही भाजपा

» महंगाई, बेरोजगारी से जनता परेशान, पुलिस हिरासत में मौत में प्रदेश नंबर वन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की नकली विकास की परतें खुलती जा रही हैं। खुद सरकारी आंकड़े भाजपा सरकार की नकारात्मक उपलब्धियों और झूठे दावों की पोल खोल रहे हैं। जहां पुलिस हिरासत में मौतों के मामलें में उत्तर प्रदेश नंबर वन है वहीं केंद्र सरकार के रोजगार संबंधी झूठ की सच्चाई भी सामने आ गई है कि किस तरह लोगों को भ्रमित करने की साजिशें भाजपा रचती है।

उन्होंने कहा कि पुलिस की हिरासत में मौत होना दरअसल हत्या के बराबर होता है। इस मामले में उत्तर प्रदेश का नंबर वन होना प्रदेश की भाजपा सरकार पर कलंक से कम नहीं है। प्रदेश में 2020 से 2021 तक पुलिस हिरासत में 451 मौतें हुई, वहीं 2021 से 2022 में ये आंकड़ा बढ़कर 501 पहुंच गया है। इस तरह 2020 से 2022 के बीच भाजपा राज में उत्तर प्रदेश में कुल 952 पुलिस हिरासत में मौतें हुई हैं। आठ साल की भाजपा सरकार में बड़ी तादाद में युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। 2014 के बाद से 22 करोड़ लोगों ने केन्द्र सरकार में नौकरी के लिए आवेदन किया है लेकिन सिर्फ 7 लाख 22 हजार 311 युवाओं को ही नौकरी मिली है। भाजपा ने दो करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था लेकिन यह वादा ही रह गया। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा सरकार युवाओं को नौकरी देने में फिसड्डी ही साबित हुई है।उन्होंने कहा कि आंकड़ों से साफ है कि भाजपा की डबल इंजन सरकारें झूठे प्रचार के सहारे अपना कार्यकाल पूरा कर रही है। प्रदेश में जंगलराज है। महंगाई, बेकारी और भ्रष्टाचार की मार से आम आदमी परेशान है। भाजपा जनरोष से बचने के लिए क्षणिक उत्तेजना वाले मुद्दे उछाल कर अपना बचाव कर रही है। उसकी मंशा सच को छुपाने और झूठ फरेब को बढ़ाने की है।

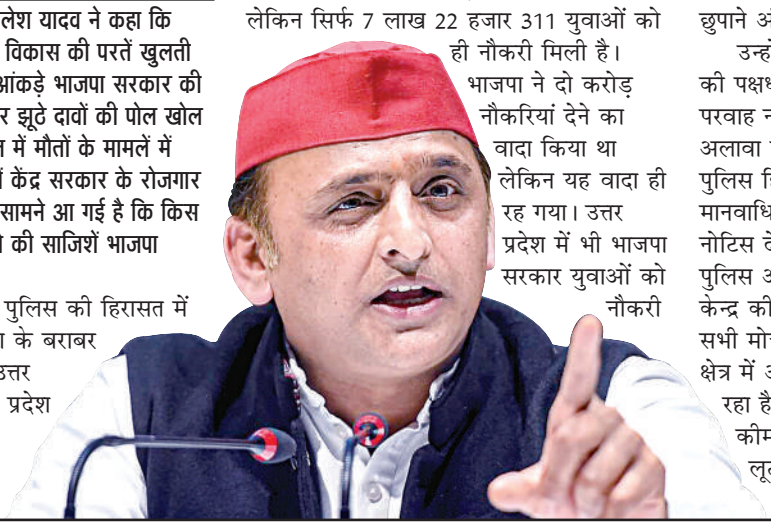

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पूंजीघरानों की पक्षधर है इसलिए उसे गरीबों की कतई परवाह नहीं है। रोजाना दुष्कर्म की घटनाओं के अलावा लूट, अपहरण और हत्याएं हो रही हैं। पुलिस हिरासत में मौतों पर राज्य सरकार को मानवाधिकार आयोग ने न जाने कितनी बार नोटिस दे चुका है। फर्जी एनकाउंटरों की जांच में पुलिस अफसर तक फंस रहे हैं। भाजपा सरकार केन्द्र की हो या उत्तर प्रदेश की दोनों विकास के सभी मोर्चों पर विफल हैं। भाजपा राज में हर क्षेत्र में आई गिरावट से देश, प्रदेश पिछड़ता जा रहा है। अर्थव्यवस्था डूब रही है, रूपये की कीमत घटती जा रही है और देश का धन लूटकर लोग विदेश भाग रहे हैं। भाजपा राज की यही उपलब्धियां हैं।

रोजगार के लिए लोन लेने में नहीं होगी दिक्कत : सहगल

» आवेदनपत्रों के निरस्तीकरण को कम करें बैंक

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को मजबूत करने के लिए कई ठोस कदम उठा रही है। अपर प्रमुख सचिव खादी एवं ग्रामोद्योग नवनीत सहगल ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आसानी से ऋण मिले।

नवनीत सहगल ने केंद्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की ओर से गन्ना संस्थान में आयोजित एक दिनी राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में उद्योग विभाग, उप्र खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड व खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने मिलकर मार्जिनमनी वितरण में 123 प्रतिशत सफलता पाई है। प्रदेश की 12581 इकाइयों को पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत 410.53 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी अनुदान व बैंकों की ओर से 1181.73 करोड़ का ऋण दिया गया है जिसके माध्यम से 1,00648 लोगों को रोजगार मिला है। पांच वर्षों में 40 हजार इकाइयां स्थापित हुई और लगभग पांच लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। अब इस योजना में ट्रेड, डेयरी, पोल्ट्री व ट्रांसपोर्ट सहित अन्य उद्योगों को शामिल किया गया है। उन्होंने सभी बैंक प्रतिनिधियों से कहा कि उनका ऋण आवेदनपत्रों के निरस्तीकरण का अनुपात अधिक है, इसे कम किया जाए।

बुंदेलखंड में धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन, सरकारी खजाने को लग रहा चूना

» 2016 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिये थे जांच के आदेश

» प्रतिबंधों और एनजीटी के आदेशों की उड़ रही धज्जियां

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

झांसी। बुंदेलखंड में प्रतिबंधों और एनजीटी के आदेशों के बावजूद धड़ल्ले से अवैध खनन का काम चल रहा है। इसके कारण सरकार के खजाने को हर साल करोड़ों का नुकसान हो रहा है। वहीं पर्यावरण, नदियां, वनस्पतियां और जीव-जंतु भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।

बुंदेलखंड में खनिज संपदा सबसे अधिक मात्रा में हैं। यहां की नदियां बालू से भरी हैं तो पहाड़ों को तोड़कर गिट्टी बनाई जाती है। इससे प्रदेश सरकार को हर महीने करोड़ों का राजस्व मिलता है। खनन को लेकर एनजीटी और सरकार के नियम हैं लेकिन उनको ताक पर रखकर कई सालों से अवैध खनन का काम हो रहा है। अधिकारी तक अवैध खनन में शामिल पाए गए हैं। नदियों में बड़ी-बड़ी मशीनों से रेत निकाला जाता है। वहीं पहाड़ों को हैवी ब्लास्टिंग कर तोड़ा जा रहा है जिससे यहां की भौगोलिक स्थिति बदलती जा रही है। महोबा की कबरई पत्थर मंडी एशिया की सबसे बड़ी पत्थर मंडी है, यहां से गिट्टी पूरे देश में जाती है। वहीं बांदा में केन, यमुना, बागे और चंद्रावल नदी से रेत निकालने को लेकर पट्टे आवंटित किए जाते हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2016 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध खनन के संबंध में जांच का आदेश जारी किया था। वहीं कैग ने वर्ष 2014-15 की रिपोर्ट में अधिकारियों की मिलीभगत से बुंदेलखंड के ललितपुर, झांसी, जालौन, महोबा, बांदा और चित्रकूट जनपदों में खदानों से अवैध खनन कर शासन को करोड़ों रुपये के चूना लगाए जाने की रिपोर्ट दी थी। सबसे बड़ा घपला पट्टा पाए कारोबारियों ने किया है। खदानों से दस साल में बिना अनुमति के अरबों रुपयों का खनिज निकाल कर बेच दिया गया। कई खदानों में बिना माइनिंग प्लान पास कराए करोड़ों के खनिज को ठिकाने लगा दिया गया जबकि माइनिंग प्लान में तय होता है कि खदान से कितना खनिज निकाला जा सकता है। वहीं झांसी के खनन अधिकारी बी.पी यादव का कहना है कि जिले में अवैध खनन पर अंकुश लगा हुआ है और अगर कोई अवैध खनन करता पाया जाता है तो उस पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाती है ।

मैंगो फेस्टिवल में 'मोदी' आम का जलवा

» नेशनल मीडिया क्लब ने मनाया देश का सबसे बड़ा मैंगो फेस्टिवल

» 14 केंद्रीय मंत्रियों सहित 150 से अधिक सांसदों ने की शिरकत

» प्रदर्शित की गई आम की 300 से अधिक प्रजातियां विजेताओं को दिए गए पुरस्कार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। नेशनल मीडिया क्लब (एनएमसी) ने बुधवार को देश के सबसे बड़े मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया। दिल्ली स्थित वेस्टर्न कोर्ट एनेक्सी में आयोजित कार्यक्रम में आमों की तीन सौ से अधिक प्रजातियों को प्रदर्शित किया गया लेकिन मोदी आम सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र रहा। महोत्सव में 14 केंद्रीय मंत्री व 150 सांसदों ने शिरकत की।

नेशनल मीडिया क्लब के संस्थापक रमेश अवस्थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन अवस्थी के नेतृत्व में मैंगो फेस्टिवल का यह 15वां आयोजन था। आयोजन संस्कृति मंत्रालय के आजादी का अमृत महोत्सव स्मरणोत्सव के तहत किया गया। महोत्सव में दशहरी से लेकर अल्फांसो, नीलम, केसर, कैसिंग्टन, चौसा, सफेदा, देसी गोला, इलाहाबादी सफेदा, मल्लिका, फजली, फजरी गोल, अम्बिका, अरुणिका, साहेब पसंद, एल्डन सहित भारत में पाए जाने वाले आमों की तीन सौ से अधिक प्रजातियां प्रदर्शित की गई लेकिन इन सबके बीच अपने आकार, रंग और खुशबू के चलते 'मोदी' आम छाया रहा और प्रदर्शनी में आए हर आम व खास के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा। मुख्य अतिथि केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन व डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने फीता काट कर मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने समारोह की अध्यक्षता की और केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणो, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने आम प्रदर्शनी के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विधि एवं न्याय राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल, रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट, शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार आदि मौजूद रहे। महोत्सव में संगीत व नृत्य की शास्त्रीय प्रस्तुतियों व राधा-कृष्ण के संगीतमय मंचन से कलाकारों ने लोगों का मन मोह लिया।

अधीर रंजन की टिप्पणी लोकतंत्र के लिए सही नहीं

» 4पीएम की परिचर्चा में प्रबुद्धजनों ने किया मंथन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। लोक सभा में सोनिया गांधी और स्मृति इरानी के बीच नोकझोंक चर्चा में है। ऐसे में सवाल उठता हैं कि सोनिया से पंगा लेकर क्या फायदा होगा स्मृति ईरानी को। इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा, राजेश बादल, डॉ. उत्कर्ष सिन्हा, कांग्रेस प्रवक्ता शुचि विश्वास और 4पीएम के संपादक संजय शर्मा ने एक लंबी परिचर्चा की।

ऋषि मिश्रा ने कहा कि अधीर रंजन बड़े नेता है। उन्हें सोच समझकर बयान देना चाहिए। राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना चाहिए। जो संसद में हुआ वह नहीं होना चाहिए। शुचि विश्वास ने कहा कि भाजपा में जो गांधी परिवार की आलोचना करें, उसे शीर्ष और शिखर पर रखा जाता है। 75 वर्षीय महिला है, जिसने पीएम पद को त्याग दिया, उससे बदतमीजी गलत है। डॉ. उत्कर्ष सिन्हा ने कहा कि आज हम देख रहे हैं कि सत्तापक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी है सदन को चलाना, वही विरोध कर रहे हैं। बयान दें अधीर रंजन माफी मांगे सोनिया गांधी। ये है क्या? स्मृति का गुस्सा ये बया करता है कि वे कहीं न कहीं अपनी बेटी पर हुए हमले को लेकर कांग्रेस को घेरा है। राजेश बादल ने कहा ये जो पूरा एपिसोड लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है। कभी गंभीर चर्चाओं के लिए संसद जानी जाती थी, अब वह गुजरे जमाने की बात हो गई है। अधीर की टिप्पणी से बवाल हुआ, उन्होंने माफी भी मांग ली है, अधीर के मुख जो शब्द निकला वह आहत करने वाला है।

परिचर्चा
रोज शाम को छह बजे देखिए 4PM News Network पर एक ज्वलंत विषय पर चर्चा

बारिश से राजधानी में कई जगहों पर जलभराव

फोटो: सुमित कुमार

लखनऊ। राजधानी में सुबह से ही टिप-टिप कर पानी बरसता रहा। कभी तेज तो कभी धीमे बरसात अलग-अलग इलाकों में हो रही है। चारबाग रेलवे स्टेशन और आलमबाग स्थित इको गार्डन रोड पर सुबह के समय हुई तेज बारिश के कारण भारी जलभराव हो गया है। अगले तीन से चार दिन तक मध्यम से तेज बारिश होती रहेगी। सुबह से रुक-रुककर हुई धीमी बारिश किसानों के लिए काफी फायदेमंद मानी जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले तीन से चार दिन अच्छी बारिश की उम्मीद है।

पीएमओ के दखल से आधी रात रुका वाराणसी डीएम का तबादला

» वाराणसी के डीएम बने रहेंगे कौशल राज शर्मा

» 24 घंटे में आदेश रद्द, शासन की पसंद है कौशल राज

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कल 13 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे। 2006 बैच के आईएएस अधिकारी और वाराणसी के जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा को प्रयागराज का कमिश्नर नियुक्त किया गया। उनकी जगह कुशीनगर के डीएम एस.राजलिंगम वाराणसी के नए जिलाधिकारी बनाए गए थे। लेकिन योगी सरकार ने देर रात फैसला लिया कि कौशल राज शर्मा वाराणसी के जिलाधिकारी बने रहेंगे।

पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जिलाधिकारी के रूप में कौशलराज शर्मा ने नवंबर 2019 में को कार्यभार ग्रहण किया था। तीन साल के कार्यकाल में उन्होंने ऐसे कई कार्य किए, जिन्हें वाराणसी में लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा। चार्ज संभालने के बाद कोरोना काल में उन्होंने वाराणसी में कोरोना संक्रमण रोकथाम के अलावा कई पीएम के महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को लेकर भी सक्रियता दिखाई और प्रदेश और राज्य सरकार से कई बार सराहना भी प्राप्त की। इसके अतिरिक्त पीएम स्वनिधि योजना में देशभर में वाराणसी के नंबर 1 होने पर पीएम द्वारा सम्मानित भी हो चुके हैं। शासन ने वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा का तबादला रद्द कर दिया है, जिसकी वजह पीएमओ का दखल बताया जा रहा है, क्योंकि वहां कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अभी निर्माणाधीन है जिसके चलते कौशल राज शर्मा को वहां से न हटाने का निर्णय लिया गया। कौशल राज शर्मा का तबादला मंडल आयुक्त के पद पर प्रयागराज किया गया था जो कि 31 जुलाई से प्रभावी होना था। तबादला रद्द होने से कुशीनगर के डीएम एस राजलिंगम का भी तबादला रद्द करना पड़ा है। इसके अलावा उन्नाव के जिला अधिकारी रविंद्र कुमार को विशेष सचिव खाद्य लखनऊ बनाया गया है। आजमगढ़ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत प्रयागराज के अगले मंडलायुक्त होंगे। उद्योग निदेशक मनीष चौहान को आजमगढ़ के मंडलायुक्त की जिम्मेदारी दी गई है।

आईएएस जूथिका ने वीआरएस के लिए किया आवेदन

आईएएस अधिकारी जूथिका पाटणकर ने वीआरएस के लिए राज्य सरकार को आवेदन दिया है। वह 1988 बैच की अधिकारी हैं। वर्तमान में भारत सरकार में तैनात हैं। उनका कार्यकाल जनवरी 2024 तक बचा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से वीआरएस के लिए आवेदन किया है। 30 साल की सेवा पूरी होने पर आईएएस अधिकारी नियमानुसार वीआरएस ले सकते हैं।

मंकीपॉक्स : संक्रमितों के संपर्क में आने वालों की 21 दिन निगरानी

» गाइडलाइन जारी, दो बार होगी पीसीआर जांच

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मंकीपॉक्स का अभी तक एक भी संक्रमित केस सामने नहीं आया है। गौतमबुद्ध नगर के एक संदिग्ध रोगी के सैंपल की रिपोर्ट भी निगेटिव आई है। ऐसे में अभी तक भेजे गए छह सैंपल में से चार सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई है। मंकीपाक्स के संक्रमण से उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। इस संबंध में दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को 21 दिन मेडिकल टीम की निगरानी में रखा जाएगा।

इसमें मास्क पहनना, हाथ साफ रखना, घावों को पूरी तरह से ढककर रखना शामिल है। लक्षण उभरने पर उनकी जांच कराई जाएगी। यूपी के संचारी रोग विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. विकासेंदु अग्रवाल की ओर से सभी जिलों को बचाव के सभी जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। 80 हजार निगरानी कमेटियों को अलर्ट कर दिया गया है। यह विदेश व दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों पर नजर रखेंगी। गौरतलब है कि मंकीपाक्स का संबंध आर्थोपाक्स वायरस परिवार से है। इस वायरल जूनोटिक बीमारी में चेचक की तरह शरीर में दाने निकल आते हैं। साथ ही बुखार, सिरदर्द व मांसपेशियों में दर्द भी होता है। यह लक्षण मिलने पर मरीज की पहले पालीमरेज चेन रिएक्शन (पीसीआर) जांच कर आर्थोपाक्स का पता लगाया जाता है। यदि रिपोर्ट पाजिटिव आती है तो मंकीपाक्स वायरस का पता लगाने के लिए रियल टाइम पीसीआर जांच कराई जाती है।

विकास पर ध्यान दे भाजपा : राकेश टिकैत

» अधीर ने गलती मान ली, अब क्या चाहती है भाजपा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने अलीगढ़ में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति पर विवादित टिप्पणी के सवाल पर कहा कि उन्होंने जानबूझकर नहीं कहा। उन्होंने हिंदी में बोलने की कोशिश की। उनसे गलती हुई, जिसे उन्होंने स्वीकार किया है। टिकैत ने कहा कि भाजपा सदन नहीं चलने देगी। जिस तरह से एक विपक्षी नेता के साथ अभद्रता की गई है, वह ठीक नहीं है।

जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष के साथ हुआ वो भी ठीक नहीं है। कोई शब्द मुंह से निकल गया और कहने वाले ने गलती मान ली, अब भाजपा क्या चाहती है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी यह भी कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रपति से मिलकर भी मांफी मांगूंगा, अब भाजपा क्या चाहती है, इस बात को बढ़ाना गलत है। भाजपा को विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। टिकैत ने कहा कि भाजपा को विकास की बात करनी चाहिए। महंगाई जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखनी चाहिए।

शिंदे सरकार का एक महीना पूरा कैबिनेट विस्तार का कोई संकेत नहीं

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार आज अपना एक महीना पूरा कर रही है। लेकिन अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि कैबिनेट विस्तार कब होगा। शिंदे ने 30 जून को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। शिंदे द्वारा शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ बगावत करने के 10 दिन बाद सरकार बनाई गई थी।

शिवसेना के 55 में से 40 विधायकों ने शिंदे का पक्ष लिया, जिसके परिणामस्वरूप शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की ढाई साल पुरानी महा विकास अघाड़ी सरकार का पतन हो गया। ठाकरे सरकार के पतन के बाद, यह व्यापक रूप से अनुमान लगाया गया था कि फडणवीस सेना के विद्रोहियों के समर्थन से तीसरी बार राज्य की बागडोर संभालेंगे। लेकिन फडणवीस ने यह घोषणा कर सबको चौंका दिया कि शिंदे अगले मुख्यमंत्री बनेंगे और वह खुद नई सरकार का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन कुछ समय बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने फडणवीस को उपमुख्यमंत्री के रूप में सरकार का हिस्सा बनने के लिए कहा। सत्ता में आने के बाद, शिंदे सरकार ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को तेजी से ट्रैक किया है, जिसे पिछली ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा बैक बर्नर पर रखा गया था।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक **बबिता चतुर्वेदी** के लिए **4पीएम** आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (यूपी) से मुद्रित एवं प्रकाशित। **प्रधान संपादक**- अर्चना दयाल, **संपादक** - संजय शर्मा, **स्थानीय संपादक** - सूर्यकांत त्रिपाठी*, **विधि सलाहकार**: सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, मोहम्मद हैदर, **वित्तीय सलाहकार**: संदीप बंसल, **कार्टूनिस्ट**: हसन जैदी, **दूरभाष**: 0522- 4078371 | **Email**: daily4pm@gmail.com | **website**: www.4pm.co.in | **RNI-UPHIN/2015/62233** डाक पंजी. सं- SSP/LW/NP-495/2018-2020
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।